



अमेरिका में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम होगा सुपर इंटेलिजेंस, ट्रंप ने किए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर

वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सुपर इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाएगा। यह घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम में की। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बदलने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति ने टेक इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ दोपहर के भोज पर हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद कार्यकारी आदेश जारी किया। बैठक में स्पेसएक्स और टेस्ला के एलन मस्क, मेटा के मार्क जुकरबर्ग, गूगल के सुंदर पिचाई और एनवीडिया के जेन्सेन हुआंग समेत कई प्रमुख सीईओ मौजूद रहे।

व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि यह बदलाव कानून की अधिकतम अनुमति के अनुसार लागू होगा। मौजूदा नियमों, अनुबंधों और पुराने दस्तावेज में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस प्रौद्योगिकी के नीति निर्धारकों को संघीय सरकार की प्रयुक्त शब्दावली को अपनाकर परिवर्तनकारी क्षमता और अमेरिकी जनता के लिए असंमित अवसरों का पिढारा खोलना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन अब एआई के स्थान पर एसआई शब्द का प्रयोग करेगा। किसी भी प्रासंगिक संदर्भ में एआई के उपयोग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने

कहा कि प्रशासन ने अमेरिकी लोगों के लिए इससे मिलने वाले असंमित लाभ को पहचानना है। उल्लेखनीय है कि यह कार्यकारी आदेश विज्ञान और तकनीक के लिए राष्ट्रपति के सहायक (एपीएसटी) को सुपर इंटेलिजेंस की संघीय परिभाषा का प्रस्ताव देने का निर्देश देता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जन्मभूमि है। अमेरिका इस नई तकनीक को आगे बढ़ा रहा है। अनुसंधान के क्षेत्र के तौर पर इसकी शुरुआत के बाद से 70 से ज्यादा सालों से इसके विकास और इस्तेमाल में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। सुपर इंटेलिजेंस नाम आज विकसित की जा रही

टेक्नोलॉजी की असली क्षमताओं को बताता है। यह ईसानी क्रिएटिविटी के नए रूपों को सामने लाता है और अमेरिकियों को वह हासिल करने के लिए सशक्त बनाता है जो पहले असंभव था। इसी के साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन की जरूरत से ज्यादा दखल देने वाली और नुकसानदेह एसआई नीति को खत्म कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में संघीय सरकार ने जेनेसिस मिशन के लिए पांच अरब डालर से अधिक राशि की घोषणा की है। यह विज्ञान, चिकित्सा, ऊर्जा और मैयुफैक्चरिंग के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी को तेजी से हासिल करने के लिए सुपर इंटेलिजेंस की क्षमता का इस्तेमाल करने की एक राष्ट्रीय पहल है।

न्यूज़ ब्रीफ

बलोचिस्तान में इमारत में विस्फोट, सेना के दो वाहनों पर हमला, पांच जवान मारे गए



क्वेटा (बलोचिस्तान) पाकिस्तान। बलोचिस्तान के नसीराबाद जिले में एक शैक्षणिक संस्थान की निर्माणाधीन इमारत को बम से उड़ा दिया गया। इसके अलावा कच्छी में सेना के दो वाहनों पर हुए हमले में पांच जवान मारे गए। बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) ने दावा किया है कि कलाल और खुजदार में मुख्य हाइवे पर उसके लड़ाकों का नियंत्रण बरकरार है। पाकिस्तान की सेना सीधा मुकाबला करने से घबरा रही है। द बलोचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ अज्ञात हथियारबंद लोगों ने नुटल थाना क्षेत्र में बलोचिस्तान रेजिडेंशियल कालेज की बन रही बिल्डिंग को बम विस्फोट कर उड़ा दिया। विस्फोट के समय में बिल्डिंग के भीतर कोई नहीं था। यह 2018 से बन रही थी। धमाके के बाद पाकिस्तानी सेना और पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया। इस बीच बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स के प्रवक्ता उरिस्तन बलोच ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि लड़ाकों ने कच्छी इलाके के छेत्री इलाके के घादर और सनी रोड पर सेना के दो वाहनों पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में पांच जवान मौके पर ही मारे गए और कई घायल हो गए। बीएलएफ प्रवक्ता मेजर घोरम बलूच ने कहा कि 28/29 सितंबर की रात करीमा आमंड असाल्ट डिवीजन की महिला कमांडरों ने क्वेटा-कराची हाइवे पर कलाल के दशत गोरान ब्लाके में रात 12 बजे नाकाबंदी कर गुजर रहे वाहनों की तलाशी ली।

फातिमा एज्जाहरा एल मंसूरी बनी मोरक्को की पहली महिला प्रधानमंत्री



रबात। मोरक्को के राजा मोहम्मद छह ने फातिमा एज्जाहरा एल मंसूरी को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उनकी पार्टी आर्थेटिसिटी एंड मार्निटी पार्टी (पीएएम) ने 23 सितंबर को हुए संसदीय चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीती हैं। शाही महल ने इसकी जानकारी दी। राजा ने एल मंसूरी को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। पेशे से वकील एल मंसूरी पिछली सरकार में आवास मंत्री और माराकेश की मेयर रह चुकी हैं। अब उन्हें गठबंधन सरकार बनाने के लिए विभिन्न दलों से बातचीत करनी होगी और मंत्रियों की सूची राजा की मंजूरी के लिए पेश करनी होगी। चुनाव में पीएएम को 97 सीटें मिलीं। उसके बाद नेशनल रैली आफ इंडिपेंडेंट्स (आरएनआई) को 66 और इतिकलाला पार्टी को 65 सीटें मिलीं। पूर्व प्रधानमंत्री अब्देलिल्लाह बेनकिराने की जरिस्ट एंड डेवलपमेंट पार्टी (पीजेडी) को 54 सीटें मिलीं। बेनकिराने ने कहा है कि उनकी पार्टी विपक्ष में रहेगी।

फिनलैंड: जहां ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आय के हिसाब से लगता है जुर्माना



फिनलैंड। दुनिया के अन्य देशों से विपरीत, फिनलैंड में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाला जुर्माना व्यक्ति की आय के आधार पर तय होता है। यहां डे फाइन सिस्टम नामक अनूठी प्रणाली लागू है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जुर्माने का आर्थिक प्रभाव हर व्यक्ति पर समान रूप से पड़े, भले ही उसकी आय कितनी भी हो। यह व्यवस्था दुनिया के ज्यादातर देशों की उस सामान्य प्रथा से अलग है, जहां ट्रैफिक उल्लंघन पर जुर्माने की राशि पहले से तय होती है और वह व्यक्ति की आमदनी से प्रभावित नहीं होती। फिनलैंड में 1921 से लागू इस व्यवस्था के तहत, सबसे पहले नियम के उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर डे फाइन यूनिट की संख्या निर्धारित की जाती है। इसके बाद, प्रत्येक यूनिट का मौद्रिक मूल्य वाहन चालक की खर्च योग्य दैनिक आय को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। इसका अर्थ है कि समान नियम तोड़ने वाले दो लोगों का समान संख्या में यूनिट मिल सकती हैं, लेकिन उनकी वित्तीय स्थिति के कारण अंतिम जुर्माने की राशि भिन्न होगी। अधिकारी आय से संबंधित सरकारी रिकार्ड का उपयोग कर जुर्माने की राशि निर्धारित करते हैं। इसी वजह से फिनलैंड में सामान्य आय वाले व्यक्ति को जहां मामूली रकम अदा करनी पड़ सकती है, वहीं बेहद धनी व्यक्तियों पर लाखों का जुर्माना लगना आम बात है।

देश का पहला रेल केबल ब्रिज

हिमालय की छती पर भारत का इंजीनियरिंग करिश्मा, अंजी केबल ब्रिज

आंकड़ों में अंजी ब्रिज की ताकत

पुल की कुल लंबाई 725 मीटर है। इसमें 473.25 मीटर लंबा मुख्य पुल है, जिसका स्पेन 290 + 1m80 + 1m75 + 1m28.25 मीटर की व्यवस्था में है। 120 मीटर लंबा सहायक पुल है। कटड़ा छोर पर 38 मीटर लंबा एप्रोच ब्रिज है और सुपरस्ट्रक्चर की लॉन्गिंग के लिए 94.25 मीटर लंबा केंद्रीय तटबंध शामिल है। पुल की कुल डेक चौड़ाई 15 मीटर है। पुल नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फाउंडेशन के शीर्ष से 193 मीटर ऊंचा एकल केंद्रीय तोरण है, जो पुल की धुरी पर संतुलन बनाए हुए है। यह एक असममित केबल-स्टेड पुल है, जिसमें 40 मीटर गहरे हाइब्रिड फाउंडेशन वाला मुख्य पायलन है। पुल को 96 केबलों की मदद से खड़ा किया गया है। इन केबलों की लंबाई 80 मीटर से लेकर 295 मीटर तक है। केबल में 31, 37 और 43 स्टैंड हैं। केबल स्टैंड की कुल लंबाई 653 किलोमीटर है, जो जम्मू से दिल्ली तक की दूरी से भी ज्यादा है। पुल पर सिंगल रेल लाइन और 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस रोड है।

पहड़ों से जंग जीतकर बना रास्ता

इस पुल को बनाना आसान नहीं था। वार्गे तरफ ऊंची हिमालयी पहाड़ियां थीं। यह क्षेत्र फॉल्ट, फोल्ड, थ्रस्ट और भूकंपीय संभावना वाला अत्यंत जटिल क्षेत्र है। यहां तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर लंबी पहाड़ी सड़क कटड़ा छोर पर जगह न होने से श्रीनगर छोर पर किए गए। कटड़ा छोर पर सुरंग टी-2 और रियासी छोर पर सुरंग टी-3 के बीच इस पुल को फंसावा इंजीनियरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी।

कितना समय और कितना पैसा लगा

इस पूरी परियोजना को मंजूरी 1994-95 में मिली थी, लेकिन अंजी ब्रिज का असली काम 2017 के बाद तेज हुआ। सभी तकनीकी बाधाओं के बावजूद 96 केबलों को केवल 11 महीनों के रिकॉर्ड समय में 26 अप्रैल 2023 को अपनी जगह पर लगाया गया। यह अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। लागत की बात करें तो अंजी ब्रिज की लागत 458 से 550 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है। पूरी उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला परियोजना की लागत 37,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

कश्मीर को क्या फायदा होगा

कनेक्टिविटी: इसके बनने के बाद कश्मीर घाटी 12 महीने देश से जुड़ी रहेगी। बर्फबारी में सड़क बंद होने पर भी ट्रेन चलेगी।

सुरक्षा: सेना के जवान और सामान तेजी से घाटी में पहुंच सकेंगे।

आर्थिक लाभ: कश्मीर के सेब, केसर और हस्तशिल्प सीधे देश के बाजारों में जाएंगे। पर्यटन में 30% से ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद है।

इंजीनियरिंग गौरव: यह पुल 213 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा और 8 तीव्रता तक के भूकंप को भी झेल सकता है।

नई कहानी की शुरुआत : अंजी केबल ब्रिज केवल लोहे और केबल का ढांचा नहीं है। यह भारत की वह नई कहानी है, जो कहती है कि हिमालय भी अब भारतीय रेलवे की रोक नहीं सकता।

सूखे और गर्मी के कारण यूरोप में आलू का संकट



पेरिस। वर्तमान समय में पूरा यूरोप आलू की फसल के गंभीर संकट से गुजर रहा है। कई प्रमुख उत्पादक देशों में आलू की पैदावार, आकार और गुणवत्ता को प्रभावित किया है। यह समस्या आई है रिकार्ड गर्मी और लंबे समय तक पड़े सूखे के कारण। हालात ऐसे हैं कि बाजार में आलू की उपलब्धता घटने के साथ कीमतों पर भी दबाव बढ़ रहा है। वियाना की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल यूरोप के कई हिस्सों में तापमान लगातार 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। जुलाई और अगस्त में कई इलाकों में लंबे समय तक बारिश नहीं हुई। उत्तरी फ्रांस के कुछ क्षेत्रों में दस सप्ताह से अधिक समय तक मापने लायक बारिश नहीं होने की बात सामने आई है। आलू जमीन के अंदर विकसित होता है और उसके लिए पर्याप्त नमी जरूरी होती है। बारिश की कमी के कारण कंदों का विकास प्रभावित हुआ और कई जगह आलू सामान्य आकार से छोटे रह गए। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे प्रमुख उत्पादक देशों में इसका असर दिखाई दे रहा है। ऊर्जा एवं जलवायु खुफिया इकाई यानी ईसीआईयू के 17 सितंबर को जारी विश्लेषण के मुताबिक, गर्मी और सूखे के कारण यूरोप में 35 लाख टन से अधिक आलू उत्पादन प्रभावित हुआ है। कुछ प्रमुख क्षेत्रों में पैदावार में 20 प्रतिशत तक की कमी का अनुमान है। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, फसल नुकसान का आर्थिक मूल्य करीब 49.8 करोड़ से 81.8 करोड़ यूरो के बीच हो सकता है।

यूएन की हकीकत दिखाने ईरान ने किया शोले के ठाकुर का उपयोग

तेहरान

अमेरिका और ईरान के बीच तनावनी के खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां अपनी जीत के दावे करते नहीं थकते, वहीं दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। इसी बीच, ईरान ने अब संयुक्त राष्ट्र पर तोखा तंज कसा है। भारत में स्थित ईरानी दूतावास ने संयुक्त राष्ट्र को निहत्था बताते हुए बालीवुड के एक मशहूर किरदार की तस्वीर साझा की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खूब चर्चा हो रही है।

दरअसल, ईरानी दूतावास ने संयुक्त राष्ट्र की कथित बेबसी को दर्शाने के लिए 1975 की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के किरदार ठाकुर बलदेव सिंह का सहारा लिया है। यह मीम सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर साझा किया गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की वास्तविक स्थिति पर कटाक्ष किया गया है।

मीम में दो तस्वीरें नजर आ रही हैं। पहली



तस्वीर पर लिखा है, स्कूल की किताबों के मुताबिक यूएन। इसमें मार्वल के सुपरहीरो डॉक्टर स्ट्रेंज की तस्वीर है, जिसे कई हाथों के साथ दिखाया गया है। ईरान ने यह कहने की कोशिश की है कि किताबों में संयुक्त राष्ट्र को हर मोर्चे पर काम करने वाली एक शक्तिशाली और सक्षम संस्था बताया जाता है। इसके विपरीत, दूसरी तस्वीर में फिल्म शोले के ठाकुर बलदेव सिंह हैं, जिनके दोनों हाथ कटे हुए थे। इस तस्वीर पर लिखा है, वास्तविकता में यूएन। यानी ईरान के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी संस्था है जो करी-देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने से बचने का भी आग्रह करता है। राज्यमंत्री ने अधिकारियों को सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने के लिए इस्तेमाल

दौरान भी संयुक्त राष्ट्र ने बार-बार दोनों देशों से तनाव कम करने और बातचीत की अपील की, लेकिन जमीनी स्तर पर वह कोई ठोस कार्रवाई करने में असमर्थ रहा। ऐसे में ईरानी दूतावास के इस मीम का सीधा संदेश यह है कि जब बड़े और शक्तिशाली देश सीधे सीधे तौर पर संघर्ष में शामिल होते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के पास कार्रवाई करने की शक्ति नहीं बचती और वह हाथ कटे ठाकुर की तरह लाचार होकर बस देखता रह जाता है। युद्ध की शुरुआत से ही ईरानी दूतावास सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहे हैं। विभिन्न देशों में स्थित ईरानी दूतावास अक्सर अमेरिका और उसके सहयोगियों पर मीम के जरिए कटाक्ष करते रहते हैं। इसे मीम डिप्लोमेसी का नाम भी दिया जा रहा है, जिसका अर्थ है मीम का उपयोग करके एक विशिष्ट नैरेटिव स्थापित करने का प्रयास करना। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ते तनाव के बीच, यह मीम डिप्लोमेसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक नई रणनीति के रूप में उभर रही है।

नेपाल के पूर्व प्रधान न्यायाधीश राणा की गिरफ्तारी पर विपक्ष का हंगामा, संसद में सरकार से मांगा जवाब



काठमांडू नेपाल के पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा को आधी रात को कथित रूप से गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिए जाने के मामले को लेकर विपक्ष ने संसद में सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा। विपक्षी सांसदों ने राणा की गिरफ्तारी को गैरकानूनी और विधि के शासन के खिलाफ कदम बताते हुए सरकार की कड़ी आलोचना की। वहीं, सत्तापक्ष के सभी सांसद इस मुद्दे पर मौन रहे। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (राप्रपा) के सांसदों ने जबरा की गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जेन-जी के नाम का दुरुपयोग करते हुए संविधान और कानून का उल्लंघन कर राणा को हिरासत में लिया गया। नेपाली कांग्रेस के सांसद आनन्द प्रसाद ढुंगाना ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा शासन शैली पंचायती व्यवस्था के दौर से भी अधिक निरंकुश दिखाई दे रही है। उन्होंने सवाल किया कि पूर्व प्रधानन्यायाधीश को रात में जाकर बिना वारंट क्यों पकड़ा गया और देश में आखिर क्या हो रहा है। ढुंगाना ने सरकार पर निरंकुशता की ओर बढ़ने और कानून की जगह मौखिक आदेश के आधार पर शासन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि राणा को किस कारण से हिरासत में लिया गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि जबरा की सुरक्षा को लेकर खतरा था तो उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए थी, उन्हें गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी। ढुंगाना ने कहा कि पहले भी जेन-जी के नाम पर सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद और राष्ट्रपति भवन में आगजनी की गई थी और अब उसी नाम पर असुरक्षा का हवाला देकर पूर्व प्रधानन्यायाधीश को हिरासत में लिया गया। विपक्षी सांसदों ने सरकार से जवाब मांगा कि जबरा को पुलिस ने आखिर क्यों हिरासत में लिया और बाद में उन्हें क्यों रिहा किया गया। विपक्षी दलों ने राणा को हिरासत में लिए जाने को लेकर सरकार की ओर से दिए गए तर्कों पर भी आपत्ति जताई है।

बांग्लादेश में सरकार ने दुर्गा पंडालों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए

ढाका (बांग्लादेश)

बांग्लादेश सरकार ने दुर्गा पंडालों की सुरक्षा के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने संबंधित मंत्रालयों, प्रशासन और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे आने वाली दुर्गा पूजा का उत्सव शांतिपूर्ण, उत्साहपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं। अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि वे सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखें। अफवाहों को रोकें और किसी भी अभ्रिय घटना की स्थिति में निष्पक्ष जांच के जरिए तुरंत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

ढाका डिप्युटी की रिपोर्ट के अनुसार, यह दिशा-निर्देश धार्मिक मामलों के मंत्रालय में हुई अंतर-मंत्रालयी तैयारी बैठक में जारी किए गए। धार्मिक मामलों के राज्यमंत्री मोहम्मद शमीम कैसर ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार हिंदू समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक त्योहार, दुर्गा पूजा के लिए सुरक्षित और उत्साहपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पूजा कल्याण ट्रस्ट के माध्यम से देश भर के पूजा पंडालों को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा आवंटित अनुदान का सही वितरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

उन्होंने पूजा पंडालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को सतर्क रहने और मूर्ति विसर्जन के दौरान उचित प्रबंधन और सुरक्षा



सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अज्ञान और प्रार्थना के समय जरूरी शांति बनाए रखने की पुरानी परंपरा को जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों को दूसरे धर्मों के दर्जे-देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने से बचने का भी आग्रह किया।

राज्यमंत्री ने अधिकारियों को सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने के लिए इस्तेमाल

को जाने वाली पुरानी या एडिट की गई तस्वीरों और वीडियो की तुरंत पुष्टि करने का भी निर्देश दिया। इस बैठक में प्रधानमंत्री के विशेष सहायक (राज्यमंत्री के दर्जे वाले) बिजोन कांति सरकार, धार्मिक मामलों के सचिव मुंशी अलाउद्दीन अल आजाद, विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों, हिंदू-बौद्ध-ईसाई कल्याण मोर्चा, कल्याण ट्रस्टों और पूजा उत्सव परिषद के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।